Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to accord special category status to Bihar.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : बिहार राज्य विकास की दौड़ में अत्यंत ही पिछड़ता जा रहा है। राज्य के अपने सीमित संसाधन होने के कारण सबसे पहले बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देकर वहाँ उद्योगों को लगाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। इस संबंध में राज्य सरकार पिछले कई वर्षों से प्रयासरत है और केद्र से आग्रह करती आ रही है, किन्तु न तो पिछली सरकार और अब न ही मौजूदा सरकार राज्य के हित की बात कर रही है। यह तो बिहार के साथ पक्षपात और घोर अन्याय किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी इसके लिए धरने पर बैठे। राज्य के दोनों सदनों से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर केद्र को भेजा गया, जो अभी तक लंबित हैं बिहार की 11 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले राज्य को अपने भाग्य के भरोसे छोड़ दिया गया है। वैसे ही राज्य का आधे से अधिक भू-भाग प्रतिवर्ष बाढ़ की मार झेलने को मजबूर है और शेष भाग में सूखे की स्थिति बनी रहती है। बिहार में पिछले 30 वर्षों से कोई भी कल-कारखाने नहीं लगे हैं, मात्र बाढ़ पावर प्लाण्ट एवं नालंदा में एक आयुध फैक्ट्री व रेल कारखाना ही है। विगत आम चुनाव के समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने राज्य की जनता को पूर्ण भरोसा दिया था कि बिहार को अगर किसी में विशेष राज्य को दर्जा देने की ताकत है, तो वह सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं। अब सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने जा रही है, फिर भी बिहार जैसे अति पिछड़े राज्य के प्रति उदासीनता समझ से परे है। पिछले कुछ वर्षों में पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष राज्य को दर्जा दिए जाने से वहाँ बहुमुखी विकास देखा जा रहा है। इसी क्रम में अन्य पिछड़े राज्यों से भी इस प्रकार की माँगें आ रही हैं। वह सर्वथा उचित है। पिछड़े राज्यों की जनता को भी न्याय मिलना ही चाहिए।

अतः केद्र सरकार से माँग करता हूँ कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देकर यहाँ भी टैक्स की छूट मिले, जिससे कि राज्य में औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित किया जा सके और हम भी देश के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर राज्य एवं देश को आगे बढ़ाने में सरकार की मदद कर सकें।